Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 02, April, 2018, pp. 439-442

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार–पुनरावलोकन एवं संभावनाएँ

रजनी मीणा*

प्रस्तावना

आर्थिक उदारीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम बैकिंग सुधारों से जुड़ता है कि देश के बैकिंग क्षेत्र पर अभी भी सरकारी बैंको का दबदबा है, परन्तु इसके बावजूद यह सच है कि बीती काफी समय से ये बैंक फंसे हुए कर्ज कि समस्या से दो चार है सरकार ने बैंको में सुधार लाने की दिशा में कुछ प्रयास भी किये है। भारत की बैंकिंग संकट और विकास के प्रभाव में नए आकार को प्रभाव में लाने के लिए वैश्विक स्तर पर ढांचागत सुधारों के मामलें में तीन नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- पहली प्राथमिकता कारपोरेट और बैकिंग क्षेत्र की हालत को सुधारना है इसके लिए गैर–निष्पादित (NPA) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में पूंजी आधिक्य का पुननिर्माण और बैंको में पूंजी आधिक्य का पुननिर्माण और बैंको कि ऋण वसूली को बेहतर बनाना होगाः

  भारत में पिछले वर्षो में बैंको के समक्ष गैर–निष्पादित परिसंपतियों (NPAs) कि समस्या काफी गंभीर हो गई है। जून 2017 के अंत में इनकी राशि 7.33 लाख करोड़ रुपये तक पंहुच गई थी। इन पर समय बैंको को उधार ली गई राशि पर समय पर ब्याज और मूलधन नहीं चुकाया गया है। आजकल NPAs कि जगह तनावग्रस्त परिसंपति राशि (Stressed assets) कि चर्चा होने लगी है जो NPAs से भी अधिक होती है क्योंकि इसमें पुराने कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए पुनः कर्ज की व्यवस्था कर दी जाती है। जिसे पूर्व कर्ज को हरा या तरोताजा (Evergrenning of loans) की संज्ञा दी जाती है।
- दूसरी प्राथमिकता में भारत को राजस्व व संबधी कदम उठाकर अपने राजकोषीय एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहियेः

  भारतीय अर्थव्यवस्था उदीयमान (Emerging) विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है वैसे आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था (Bright economy) का स्थल माना जाने लगा अतः हमें भावी विकास कि संभावनाओं का भरपूर उपयोग करके वृद्वि–दर को सुस्थिर विकास के 8ः व अधिक के स्तर पर ले जाने का भरसक प्रयास करना चाहिए।
- भारत की तीसरी प्राथमिकता के मुताबिक बुनियादी ढ़ाँचा अंतर को पाटने के लिए ढाँचागत सुधारों की गति बनाए रखना और श्रम एवं उत्पाद बाजार की क्षमता का विस्तार होना चाहिए साथ ही कृषि सुधारों को भी आगे बढ़ाना चाहिएः

  केन्द्र के साथ–साथ राज्यों का राजकोषीय घाटा भी सीमा में रखा जाना चाहिए क्योंकि कृषको के लिए बकाया कर्ज की माफी के प्रस्तावों को लागू करने एवं राजकोषीय कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने से राज्यों की वित्तीय संपति पर काफी भार पड़ेगा और

* UGC NET Qualified (Academician)

उनका राजकोषीय घाटा काफी बढ़ जायेगा इसलिए देश को राजकोषीय घाटे को GDP के 3ः पर स्थिर करने को चुनौती का सामना करना पड़ेगा इसके बिना वृद्वि–दर को ऊँचा करना कठिन होगा।

- इसलिए फिलहाल निराशा की कोई संपति नहीं मानी जा सकती हालांकि भारत जैसे 125 करोड़ देशवासियों के मुल्क में विकास की चुनौतियों व उसकी चिंताएँ भी अनके है और रहेगी।
- Key Word: NPAs, Stressed assets, CRR, SLR, Assets Reconstruction Fund, GST, Ever greening of Loans, Recapitalization.

परिचय

प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र कि तरह बैकिंग गतिविधियों को भी सरकार रिजर्व बैंक के जरिये करती थी जिसके कारण बैकिंग क्षेत्र में कई समस्यायें उभर कर सामने आई बैकों को सरकारी नियन्त्रण के अधीन रखा गया उन्हैं सरकार द्वारा तय प्राथमिकता के अनुरुप कार्य करना पड़ता था जिसका असर उनकी लाभदायकता पर और जिनी क्षेत्रों के प्रवेश पर पांबदी के कारण बैकों का पूंजी–आधार सीमित था तथा साथ ही नकद आरक्षित अनुपात (CRR) साविधिक सरलता (SLR) प्राथमिक क्षेत्र ऋण नीति और ब्याज दरों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण बैकों की कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभदायकता पर नकारात्मक असर पड़ता है।

वर्ष 1990 तक राजनीतिक दबावों एवं सरकारी हस्तक्षेप के कारण गैर–निष्पादित परिसम्पतियाँ (NPAs) गम्भीर हो गई इससे ग्राहक सेवा अकुशल एवं अपर्याप्त थी रिजर्व बैंक के जरिये ब्याज दरों पर सरकार का नियंत्रण था इसका समेकित परिणाम बैंको की खराब आर्थिक स्थिति के रुप में हुआ भारत में बैकों की स्थिति पर अध्ययन करने पर इस सेक्टर में सुधार के लिए नरसिंहम समिति (1991) समिति का गठन किया गया। हम समिति ने अध्ययन के पश्चात अपनी सिफारिशों में पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय से पूर्व देश में वित्तिय व्यवस्था को विकसित करना बैंको की गुणवता में सुधार लाना, गैर निष्पादित परिसम्पतियाँ (NPAs) में कमी लाने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्वि करने, बैंक की खराब परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए एक Assets Reconstruction Fund की स्थापना करने एवं बैंक कर्मियो के विरुद्व किसी भी कार्यवाही से पूर्व समुचित जाँच–पड़ताल पर बल दिया। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI) के पूर्व गर्वनर एवं नरसिंहम की अध्यक्षता में वित्तिय प्रणाली ढाँचे व्यवस्था एवं कार्यशैति के सभी पहलुओं की जाँच के लिए एक समिति की नियुक्ति की इस समिति ने नवम्बर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का इतिहास

- **प्रथम नरसिंहम समिति का गठन (1991)**
  - नरसिंहम समिति प्रथम ने नकद आरक्षित अनुपात (ब्त्) की दर को 15 प्रतिशत घटाकर 8 प्रतिशत तक लाने की बात कही।
  - ब्याज दरों का निर्धारण बाजार द्वारा करने की अनुशंषा की गई।
  - गैर–निष्पादित परिसम्पतियों (छच्े) की समस्या से निपटने के लिए ऋण–वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना।
  - गैर–निष्पादित परिसम्पतियों की अधिकतम सीमा को 180 दिन निर्धारित करने की सिफारिश की।
- **द्वितीय नरसिंहम समिति का गठन (1998)**
  - मजबूत बैकिंग प्रणाली की आवश्यकता।
  - परिमित बैकिंग प्रयोग।
  - छोटे स्थानीय बैकों की स्थापना।
  - पूंजी पर्याप्त अनुपात को उन्नत करना।
- बैकों में ग्राहक सेवा सुधारने गोईपोरिमा समिति का गठन सितम्बर 1990 में किया गया।
- बैकों में ग्राहक सेवा स्तर में सुधार के लिए दामोदरन समिति का गठन वर्ष 2010 में किया गया।

उद्देश्य

बैकिंग क्षेत्र में उदेद्श्यपूर्ण सुधार (1992–2006)

- कानूनी तरलता अनुपात
- नकद आरक्षण अनुपात
- ब्याज दर के विभिन्न भाग या स्तर
- विवेकपूर्ण मापदण्ड
- पूंजी बाजार तक पंहुच
- कार्य संचालन की स्वतंत्रता
- नए निजी क्षेत्र के बैंक
- वाणिज्यिक बैकों का पर्यवेक्षण
- ऋणों की वसूली

Models

- **बेसल मानकः** बेसल स्विटजरलैण्ड का एक शहर है जहॉ बैकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अन्तराष्ट्रीय स्वरुप देने के संबध में मानक निर्धारित किए गये, जिसे बेसल मानक कहा गया।
- **बेसल मानक–I :** 1980 में यह तय किया गया, जो बैकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और मुख्यतः ऋण जोखिम पर केन्द्रित था।
- **बेसल मानक–II:** 2004 में अन्तराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैकों व वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में (9.0:) धनराशि को अपने पास सुरक्षित तय किये गये ताकि विभिन्न वित्तीय जोखिम बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगें।
- **बेसल–III:** 2010 का उद्देश्य बैकिंग क्षेत्र के लिए उच्च पूंजी आवश्यकता तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करना है। जिससे आर्थिक मंदी को रोका जा सके।

चुनौतियाँ

वर्तमान सुधारवादी योजनाऍः–

- **आर्थिक और वित्तीय स्थिरीकरणः** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था की ऐसी तस्वीर पेश की जहॉ मुद्रास्फिति बढ़ रही है जबकि वृद्वि में कमी आई है और आगे इसके और धीमा होने की आशंका यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूा मंदी नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे बदलावपरक कारको के चलते आई या फिर यह दीर्घावधि की ढॉचागत वजहो मसलन बैकिंग व्यवस्था के फंसे हुए कर्ज और अत्यधिक नकदी वाले कारोबारी क्षेत्र की वजह से है आरबीआई (RBI) ने निजी निवेश को तेज करने की बात दोहराई है और कहा है कि उसकी मदद से ही अर्थव्यवस्था और समग्र ऋण की स्थिति बेहतर की जा सकती है। यह सच है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में हाल के महीनों में मांग के सुधार देखने को मिला है परन्तु उक्त अनुमान अभी भी अत्यधिक आशावादी नजर आता है और आशावादी नजरिया कहता है कि
  - त्यौहारी मौसम में खपत बढ़ेगी।
  - जीएसटी के क्रियान्वयन की दिक्कतें भी समाप्त होगी।
  - विमुद्रीकरण का असर कम
- **सरकारी बैकों के मर्जर के लिए समिति का गठनः–** सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की स्थिति सुधारने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार ने जेटली के नेतृत्व में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन कर दिया है यह समिति देश के 21 फरवरी सरकारी बैकों के विलय प्रस्ताव पर गोर करेगी वैकल्पि प्रणाली का गठन इस दिशा में उठाया कदम है। 2017 अगस्त महीने में केन्द्रीय मंत्रीपरिषद ने पीएसयू बैकों के एकीकरण की तेजी से ट्रेक करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था खराब पूंजी की समस्या से जूझ रहे

बैंक जिनका एकीकरण किया जाना है उनकी कुल बाजार हिस्सेदारी 70 फीसदी थी जबकि भारत के बैकिंग सिस्टम में उनके बैड लोन की हिस्सेदारी 80 फीसदी की है।

- **बैकों के लिए पुनःपूंजीकरण का कार्यक्रमः–** सरकार द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम का दूसरा भाग बैकों के लिए पुनः पूंजीकरण से सम्बन्धित है भारत में पिछले वर्षो में बैंको के समक्ष गैर–निष्पादित परिसम्पतियों (NPAs) की समस्या काफी गंभीर हो गई जुन 2017 के अंत में इनकी राशि 7.33 लाख करोड़ रुपये तक पंहुच गई थी इन पर समय पर ब्याज और मूलधन नहीं चुकाया गया है, जिसमें बैकों की वित्तीय स्थिति पर विपरित प्रभाव उत्पन्न हुआ है। आजकल NPAs की जगह तनावग्रस्त परिसम्पति राशि (Stressed Assets) की चर्चा होने लगी है जो NPAs से भी अधिक होती है क्योंकि इससे पुराने कर्ज को पुर्नगठित करने के लिए पुनः कर्ज की व्यवस्था कर दी जाती है जिसे पूर्व कर्ज को हरा या तरोताजा (Evergreening of Loans) की संज्ञा दी जाती है। बैकों के लिए पुनः पूंजीकरण की व्यवस्था से उनकी उधार देने की क्षमता का विस्तार होगा जो सितम्बर 2017 के अंत में मात्र 7 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इस प्रकार 2.11 लाख करोड़ रुपये बैकों को पूंजी प्रदान करने का यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी से काफी काम करेगा और साथ में बेसल–II के लिए पूंजी मानको को पूरा करने में भी बैकों को पर्याप्त सुविधा देगा।
- **बैकों के लिए रीकेप प्लानः–** सरकारी बैकों के बढ़ते NPAs की वजह से उनकी प्रदर्शन पर नकारात्मक असर हो रहा है जिसकी वजह से सरकार ने हाल ही में सरकारी बैकों के लिए रीकेपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके तहत बैकों को 2 साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये दिये जायेगें। बैंक रीकेपिटलाइजेशन के लिए सरकार मौजूदा वित्त वष के अंत तक 80 हजार करोड़ के बॉण्ड जारी करेगी इस एवज में संसद ने अपनी मंजूरी दे रही है। सरकार ने संसद में अतिरिक्त खर्चे के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिए मंजूरी मांगी थी।
- **भारत में आर्थिक धीमापन व सुधार हेतु सरकार का राजकोषीय प्रयासः–**इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक सुधारो से अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में कई प्रकार दबाव व तनाव उत्पन्न हुए है देश में अनिश्चितता व अल्पकालीन अस्थिरता की स्थिति बनी है जो अस्वाभाविक नहीं मानी जा सकती है। इनसे ग्रोथ रेट पर भी विपरीत प्रभाव उत्पन्न हुआ है। विमुद्रीकरण व जीएसटी दोनों बड़े क्रांतिकारी आर्थिक कदम माने गए है। इन्होनें एक बार तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। अतः अब यह देखना है कि वर्तमान आर्थिक धीमेपन को दूर करने के लिए क्या ठोस उपाय अपनाने चाहिये GDP की वृद्वि–दर को ऊँचा करने की लिए निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थिर पूंजी–निर्माण, शुद्व–निर्यातो आदि की वृद्वि दरों को बढ़ाना जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था 2018–19 व बाद के वष्रे में पुनः ऊँची वृद्वि दरों की और अग्रसर हो सकेगी।

निष्कर्ष

बैकिंग जगत में तनावग्रस्त परिसंपतियो की भारी समस्या के रहते मात्र ब्याज की दर के घटने से निवेश वृद्वि के लिए अनुकूल वातावरण सृजित नहीं हो पाता निजी निवेश को बढ़ाने के लिए उधमकर्ताओं में भारी जोश व विश्वास बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता मानी गई ताकि देश में निजी निवेश बढ़ सके इसके लिए कई तत्वों की आवश्यकता होती है जैसे वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने की दशा उत्पन्न हो उद्योगों में लाभ की प्रत्याशित दर उंची हो उधमकर्ताओं को शेयर बाजार व वित्तीय संस्थाओं से उधार की पर्याप्त व्यवस्था हो देश में ऊँची ग्रोथ रेट का वातावरण पाया जाये।

संदर्भ

- विकिपीडिया।
- प्रतियोगिता टुडे।
- न्यूज पेपर।
- पुस्तकें।

♦❐♦